evaluation studies of various Central/ Centrally Sponsored Schemes on All India basis. In some of these studies North Eastern States have been covered. The list of the evaluation studies conducted during the last five years and in which North Eastern States have been covered is at statement-II. *(see below).*

(c) Does not arise.

Statement-I

Sl. No.	NAME OF THE SCHEME
1.	Employment Assurance Scheme.
2.	Supply of Improved Tool Kits to Rural Artisans.
3.	One Million Houses under Indira Awas Yojana.
4.	Revamped Public Distribution System (RPDS).
5.	Prime Minister's Rozgar Yojana
6.	Indira Mahila Yojana
7.	Mahila Samridhi Yojana
8.	National Programme of Nutrition Support to Primary Education.
9.	Special Area Scheme for Special Sectors.
10.	National Social Assistance Programme.
11.	Mid Day Meal Programme*

* Reviewed in the State of Assam and Meghalaya only

Statement-II

Sl. No.	Name of Evaluation Study	Name of North-Eastern States covered in the Sample
1.	Study of the Domestic Industries Centres Programme	Assam, Manipur
2.	Evaluation Study on Revamped Public Distribution System	Assam, Arunachal Pradesh
3.	Evaluation Study on Mahila Samridhi Yojana	Assam, Arunachal Pradesh
4.	Evaluation Study on Accelrated Rural Water Supply Programme	Assam, Meghalya

गैर-सरकार पार्टियों द्वारा तेल निकाला जाना

1428. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:**
श्री महेश्वर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से तेल कुओं की खोज की गई है;

(ख) क्या इनमें से किसी भी कुएं से तेल-दोहन का कार्य गैर-सरकारी पार्टियों को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम इनके दोहन का कार्य पुनः अपने हाथ में लेने का विचार रखता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) पिछले दो वर्षों (1994-95 और 1995-96) के दौरान, ओ आई एल और ओ एन जी सी के अन्वेषणात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित नई संभावनाओं में तेल की खोज की गई:—

क्र० सं०	संभावना	बेसिन
	तटीय	
1.	खंबोई	कैम्बे बेसिन
2.	पुडी	कावेरी बेसिन
3.	किझाहतुर	-वही-
4.	भेकुलाजान	असम
5.	रजाली	-वही-
6.	बोरहपजान	-वही-
7.	रूंगालीटिंग	-वही-
8.	तमुलीखत अपतटीय	-वही-
9.	बी-15	बंबई अपतट
10.	जी एस-23	के जी अपतट
11.	बी-193	बंबई अपतट
12.	बी-153	-वही-
13.	डब्ल्यू ओ-15	-वही-
14.	डब्ल्यू ओ-16	-वही-
15.	बी-15 ए	-वही-

(ख) उपर्युक्त में से कोई भी संभावना निजी पक्षकारों को नहीं दी गई है।

(ग) से (ङ) भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवनों में अतिरिक्त मंजिल

1429. **श्री पराग जानिलाः**
श्री गोविन्दराम मिरीः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चार से कम मंजिल वाले डी० डी० ए० भवनों में एक अतिरिक्त मंजिल के निर्माण की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त उत्तर के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान धनराशि का उपयोग न किया जाना

1430. **श्री राम जेठमलानीः** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1996 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "स्टेट्स स्लिप ऑन टार्गेट्स फॉर प्लान एक्सपेंडीचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित की गई राशि का उपयोग नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक चार वर्षों के दौरान विकास योजनाओं के लिए आवंटित की गई राशि का पचास प्रतिशत से कम उपयोग किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र केo अलघ): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के ही वास्तविक योजना व्यय के आंकड़े उपलब्ध हैं। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ राज्यों का व्यय प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमोदित परिव्यय से कम रहा है। बहरहाल, यदि केवल बिहार राज्य के प्रथम दो वर्षों के योजना व्यय के आंकड़े तथा परवर्ती दो वर्षों के संशोधित परिव्यय पर ध्यान दें, तो कुल व्यय/प्रत्याशित व्यय आठवीं योजना के प्रथम चार वर्षों के लिए मूलतः अनुमोदित परिव्यय से 50 प्रतिशत कम है।

Time Bound Programme for Sanitation

1431. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether nearly 96 percent of rural and 52 percent of urban population is not yet covered with sanitation facilities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether any time-bound programme has been chalked out to